Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Research (JIMR)
E-ISSN:1936-6264| Impact Factor: 8.886| UGC CARE II
Vol. 20 Issue 09, Sep- 2025
Available online at: https://livejimrjournal.in/
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

भारत–बांग्लादेश साझेदारी का सार्क पर प्रभाव : यूपीए व एनडीए काल का तुलनात्मक अध्ययन

राकेश कुमार
शोधार्थी (राजनीति विज्ञान)
महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

डॉ. नूरजहाँ
सह–आचार्य (राजनीति विज्ञान)
राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर

सारांश

भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की दिशा और प्रभावशीलता में अत्यंत निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दोनों देशों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और भौगोलिक संबंध सार्क के सहयोगात्मक ढांचे की नींव को मजबूत बनाते हैं। प्रस्तुत शोधपत्र में 2004 से 2022 के मध्य संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) शासनकाल में भारत–बांग्लादेश साझेदारी के विकास और उसके सार्क पर प्रभाव का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। यूपीए काल (2004–2014) में दोनों देशों के संबंधों में पारस्परिक विश्वास और संवाद की भावना दिखाई दी। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत ने व्यापार, ऊर्जा, सीमा प्रबंधन, जल–वितरण और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्रों में कई समझौते किए। इस अवधि में सार्क को भारत–बांग्लादेश सहयोग से नई ऊर्जा मिली और दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय एकता की भावना सशक्त हुई। इसके विपरीत, एनडीए काल (2014–2022) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "Neighbourhood First Policy" के अंतर्गत भारत–बांग्लादेश संबंध और अधिक व्यावहारिक एवं रणनीतिक रूप में विकसित हुए। 2015 के भूमि सीमा समझौते (Land Boundary Agreement) ने दोनों देशों के बीच दशकों पुराने विवाद का समाधान किया, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा मिला। हालाँकि सार्क मंच पर पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के कारण संगठन की सक्रियता कम हुई, फिर भी भारत–बांग्लादेश सहयोग ने द्विपक्षीय स्तर पर क्षेत्रीय प्रगति की भावना को बनाए रखा।

मुख्य शब्दः भारत, बांग्लादेश, सार्क, दक्षिण एशिया, यूपीए शासन, एनडीए शासन, क्षेत्रीय सहयोग, विदेश नीति, भूमि सीमा समझौता, नेबरहुड फर्स्ट नीति, आर्थिक साझेदारी, रणनीतिक संबंध

प्रस्तावना

Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Research (JIMR)
E-ISSN:1936-6264| Impact Factor: 8.886| UGC CARE II
Vol. 20 Issue 09, Sep- 2025
Available online at: https://livejimrjournal.in/
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

भारत और बांग्लादेश के संबंध दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण आयामों में से एक हैं। दोनों देशों के बीच साझा इतिहास, सांस्कृतिक निकटता, भाषायी समानता और भौगोलिक जुड़ाव न केवल द्विपक्षीय संबंधों की गहराई को दर्शाते हैं, बल्कि दक्षिण एशियाई सहयोग की संभावनाओं को भी नई दिशा प्रदान करते हैं। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण में भारत की निर्णायक भूमिका के कारण दोनों देशों के संबंधों की नींव पारस्परिक विश्वास और सहयोग पर आधारित रही है। इसी विश्वास की पृष्ठभूमि में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की स्थापना वर्ष 1985 में की गई, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय विकास, आर्थिक साझेदारी और राजनीतिक स्थिरता को प्रोत्साहित करना था।

सार्क का गठन इस विचार पर आधारित था कि दक्षिण एशिया के देश यदि आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर संवाद, सहयोग और साझा विकास के मार्ग पर चलें तो यह क्षेत्र गरीबी, असमानता और अविकास जैसी समस्याओं से मुक्ति पा सकता है। भारत और बांग्लादेश सार्क के दो ऐसे देश हैं जिनका आपसी सहयोग संगठन की दिशा और प्रभावशीलता को गहराई से प्रभावित करता है। भारत जहाँ क्षेत्रीय शक्ति के रूप में नेतृत्व की भूमिका निभाता है, वहीं बांग्लादेश अपनी भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, और सांस्कृतिक विरासत के कारण सार्क में एक सक्रिय और संतुलनकारी सदस्य के रूप में उभरा है।

वर्ष 2004 से 2022 तक की अवधि भारत–बांग्लादेश संबंधों के विकास और उनके सार्क पर प्रभाव को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। इस अवधि में भारत की विदेश नीति ने दो स्पष्ट चरणों को देखा– संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) का शासन (2004–2014) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का शासन (2014–2022)। यूपीए शासनकाल में भारत ने बहुपक्षीय सहयोग, विश्वास निर्माण और क्षेत्रीय एकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत ने सार्क को क्षेत्रीय संवाद और आर्थिक साझेदारी के मंच के रूप में सक्रिय रखा। इस दौरान बांग्लादेश के साथ व्यापार, ऊर्जा, शिक्षा, जल–वितरण और सीमा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में कई ऐतिहासिक समझौते हुए। इस सहयोग ने सार्क को नई ऊर्जा प्रदान की और दक्षिण एशियाई एकता की भावना को प्रबल बनाया।

दूसरी ओर, एनडीए शासनकाल में भारत की विदेश नीति का स्वरूप अधिक रणनीतिक और व्यावहारिक हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने "Neighbourhood First Policy" के तहत दक्षिण एशिया में संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में कई ठोस कदम उठाए। विशेष रूप से 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता (Land Boundary Agreement) हुआ, जिसने दशकों पुराने विवाद का समाधान कर क्षेत्रीय स्थिरता में नया अध्याय जोड़ा। इसके साथ ही व्यापारिक कनेक्टिविटी, ऊर्जा सहयोग और जल परिवहन जैसे क्षेत्रों में भी दोनों देशों ने नए अवसरों को जन्म दिया। हालाँकि, पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव और आतंकवाद की चुनौतियों के कारण सार्क की गतिविधियाँ सीमित हो गईं, फिर भी भारत–बांग्लादेश सहयोग ने क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग की भावना को जीवित रखा।

भारत–बांग्लादेश संबंधों की निरंतरता ने दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की धारणा को नई दिशा दी है। जहाँ यूपीए काल में यह संबंध संवाद और सांस्कृतिक निकटता पर आधारित था, वहीं एनडीए काल में यह संबंध रणनीतिक साझेदारी और परस्पर हितों पर केंद्रित हुआ। इन दोनों कालखंडों का तुलनात्मक अध्ययन इस तथ्य को उजागर करता है कि भारत और बांग्लादेश का सहयोग केवल द्विपक्षीय सीमा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने सार्क की संरचना, नीतियों और भविष्य की दिशा को गहराई से प्रभावित किया।

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य इसी परिवर्तनशील यात्रा का विश्लेषण करना है कि किस प्रकार भारत–बांग्लादेश साझेदारी ने सार्क की नीतियों, उद्देश्यों और सक्रियता को प्रभावित किया। इसमें यूपीए और एनडीए शासनकाल की नीतियों, कूटनीतिक दृष्टिकोणों और क्षेत्रीय परिणामों की तुलनात्मक समीक्षा की जाएगी। अध्ययन इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करता है कि क्या भारत–बांग्लादेश सहयोग सार्क के पुनर्जीवन की कुंजी बन सकता है और क्या इस साझेदारी के माध्यम से दक्षिण एशिया में स्थायी शांति और आर्थिक एकता की नई संभावनाएँ उभर सकती हैं।

आज जब दक्षिण एशिया में चीन की आर्थिक सक्रियता, पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता और वैश्विक शक्ति–संतुलन की बदलती परिस्थितियाँ नई चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रही हैं, तब भारत–बांग्लादेश साझेदारी का महत्व और भी बढ़ गया है। यह केवल दो देशों का संबंध नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की सामूहिक प्रगति और स्थिरता का आधार है। अतः यह अध्ययन इस धारणा को पुष्ट करता है कि भारत–बांग्लादेश सहयोग सार्क के पुनर्जीवन और दक्षिण एशिया में स्थायी विकास की दिशा में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

यूपीए शासन (2004–2014) में भारत–बांग्लादेश सम्बन्ध और सार्क पर प्रभाव

वर्ष 2004 से 2014 तक का काल भारत और बांग्लादेश के संबंधों के इतिहास में एक सहयोगात्मक, संवाद–प्रधान और पारस्परिक विश्वास से भरा हुआ दशक था। इस अवधि में भारत में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की सरकार सत्ता में थी और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में विदेश नीति का मूल आधार था– "पड़ोसी पहले" (Neighbourhood First)। इस नीति के अंतर्गत भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ स्थायी संबंधों के निर्माण के लिए संवाद, आर्थिक साझेदारी और क्षेत्रीय सहयोग को प्राथमिकता दी। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों में इस दौरान उल्लेखनीय सुधार हुआ, जिसने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की दिशा और प्रभाव को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित किया।

यूपीए शासनकाल में भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती का सबसे बड़ा आधार था– विश्वास का पुनर्निर्माण। 2009 में बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व में अवामी लीग सरकार के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के बीच राजनीतिक दृष्टिकोण और सुरक्षा हितों में समानता दिखाई देने लगी। भारत ने बांग्लादेश की आंतरिक स्थिरता, आतंकवाद–निरोधक प्रयासों और आर्थिक विकास के लिए व्यापक सहयोग प्रदान किया। बांग्लादेश ने भी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय उग्रवादी समूहों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की, जिससे सुरक्षा सहयोग की नींव और मजबूत हुई।

आर्थिक दृष्टि से यूपीए शासन के दौरान भारत–बांग्लादेश व्यापारिक संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। दोनों देशों ने सार्क मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) के ढांचे के अंतर्गत परस्पर व्यापार को बढ़ावा दिया। भारत ने बांग्लादेश को निर्यात में रियायतें दीं और कई उत्पादों पर शुल्क–मुक्त पहुँच प्रदान की। इसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का भारत के साथ व्यापारिक घाटा कम हुआ और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी अधिक संतुलित हुई। यह क्षेत्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा कदम था, जिसने सार्क के आर्थिक उद्देश्यों को सशक्त किया। ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। भारत और बांग्लादेश ने विद्युत आदान–प्रदान समझौते (Power Exchange Agreement) पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति प्रारंभ हुई। यह दक्षिण एशिया के देशों के बीच ऊर्जा साझेदारी

Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Research (JIMR)
E-ISSN:1936-6264| Impact Factor: 8.886| UGC CARE II
Vol. 20 Issue 09, Sep- 2025
Available online at: https://livejimrjournal.in/
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

का एक मॉडल बना, जिसे सार्क मंच पर सार्क ऊर्जा ग्रिड (SAARC Energy Grid) के रूप में आगे बढ़ाने की योजना बनी। इससे क्षेत्रीय एकीकरण की भावना को बल मिला।

जल–वितरण और सीमा प्रबंधन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी यूपीए काल में सकारात्मक संवाद हुआ। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल–वितरण समझौता पर विचार–विमर्श हुआ, जो यद्यपि औपचारिक रूप से हस्ताक्षरित नहीं हो सका, लेकिन इस संवाद ने आपसी विश्वास में वृद्धि की। सीमावर्ती प्रबंधन, तस्करी रोकथाम और सीमा चिह्नांकन जैसे मुद्दों पर संयुक्त कार्यबल गठित किए गए, जिससे सीमा क्षेत्रों में स्थिरता और सहयोग बढ़ा। सांस्कृतिक और जन–स्तरीय संबंधों के क्षेत्र में भी यह काल अत्यंत सशक्त रहा। यूपीए शासनकाल में दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम, शैक्षणिक छात्रवृत्तियाँ और साझा ऐतिहासिक स्मृतियों पर आधारित उत्सवों का आयोजन हुआ। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की स्मृति और शहीदों के प्रति भारत की संवेदनशीलता ने द्विपक्षीय संबंधों को भावनात्मक गहराई प्रदान की। इस सांस्कृतिक निकटता ने सार्क के सामाजिक सहयोग आयाम को सशक्त किया, जो क्षेत्रीय एकता के लिए अत्यंत आवश्यक था।

सार्क के स्तर पर देखा जाए तो यूपीए शासनकाल के दौरान भारत और बांग्लादेश का सहयोग संगठन की सक्रियता का आधार बना। दोनों देशों ने 2005 (ढाका), 2007 (नई दिल्ली) और 2010 (थिम्पू) में आयोजित सार्क शिखर सम्मेलनों में गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, और स्वास्थ्य सहयोग जैसे विषयों पर संयुक्त रूप से पहल की। भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर सार्क विकास कोष (SAARC Development Fund) की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई, जो दक्षिण एशिया की सामाजिक परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता था।

यूपीए शासनकाल की विदेश नीति का मूल स्वभाव सहयोगात्मक कूटनीति (Cooperative Diplomacy) का था। भारत ने सार्क के भीतर अपने प्रभाव का उपयोग दबाव के रूप में नहीं, बल्कि प्रेरणा के रूप में किया। इस दृष्टिकोण ने छोटे सदस्य देशों–विशेषतः बांग्लादेश, नेपाल और भूटान– के भीतर भारत के प्रति विश्वास और सम्मान को मजबूत किया। डॉ. मनमोहन सिंह ने 2011 में ढाका की यात्रा के दौरान कहा था कि "भारत का विकास तभी सार्थक है जब उसके पड़ोसी भी प्रगति करें।" यह कथन उस युग की विदेश नीति की आत्मा को अभिव्यक्त करता है।

इस प्रकार, यूपीए शासनकाल में भारत–बांग्लादेश संबंधों ने न केवल द्विपक्षीय स्तर पर विश्वास और साझेदारी को गहराई दी, बल्कि सार्क को भी नई दिशा और सक्रियता प्रदान की। दोनों देशों की साझेदारी ने क्षेत्रीय सहयोग की भावना को व्यावहारिक रूप दिया, जिससे सार्क दक्षिण एशिया में साझा विकास का प्रतीक बन सका। यह काल सार्क के इतिहास का वह दौर रहा जब भारत–बांग्लादेश सहयोग संगठन की आत्मा के अनुरूप उसकी वास्तविक प्रगति का आधार बना।

एनडीए शासन (2014–2022) में भारत–बांग्लादेश सम्बन्ध और सार्क पर प्रभाव

Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Research (JIMR)
E-ISSN:1936-6264| Impact Factor: 8.886| UGC CARE II
Vol. 20 Issue 09, Sep- 2025
Available online at: https://livejimrjournal.in/
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार के गठन के साथ भारत की विदेश नीति में एक नई सक्रियता और रणनीतिक दृष्टि का आरंभ हुआ। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत "Neighbourhood First Policy" के साथ की, जिसका उद्देश्य था पड़ोसी देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को मज़बूत करना। इस नीति का प्रभाव भारत–बांग्लादेश संबंधों में विशेष रूप से दिखाई दिया। दोनों देशों के बीच सहयोगात्मक संबंधों में एक नई ऊर्जा आई जिसने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की दिशा और प्रभावशीलता पर गहरा प्रभाव डाला।

एनडीए शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि रही वर्ष 2015 का भारत–बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता (Land Boundary Agreement - LBA)। यह ऐतिहासिक समझौता दोनों देशों के बीच 40 वर्षों से लंबित सीमा विवाद को समाप्त करने वाला कदम था। इसके तहत दोनों देशों के बीच 162 एनक्लेवों का आदान–प्रदान हुआ और सीमा को औपचारिक रूप से चिन्हित किया गया। इस समझौते से न केवल सीमा क्षेत्रों में स्थिरता आई बल्कि भारत और बांग्लादेश के बीच विश्वास का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। यह कदम दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध हुआ और सार्क की सहयोगात्मक भावना को नई दिशा मिली।

आर्थिक दृष्टि से भी मोदी सरकार के काल में भारत–बांग्लादेश संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। दोनों देशों के बीच व्यापार का आकार लगभग दोगुना हुआ और भारत बांग्लादेश का प्रमुख व्यापारिक साझेदार बन गया। सीमा पार व्यापार, सड़क एवं रेल संपर्क (Connectivity) और जलमार्गों के माध्यम से परिवहन को पुनर्जीवित किया गया। कोलकाता–ढाका बस सेवा और अखौरा–अगरतला रेल परियोजना जैसी पहलों ने दोनों देशों को और निकट लाया। इन प्रयासों ने दक्षिण एशिया में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया, जिससे सार्क के आर्थिक उद्देश्यों को भी अप्रत्यक्ष रूप से बल मिला।

ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ दर्ज की गईं। भारत से बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति में वृद्धि हुई और भारत–बांग्लादेश ऊर्जा ग्रिड कनेक्शन का विस्तार किया गया। साथ ही फरीदपुर–त्रिपुरा गैस पाइपलाइन परियोजना जैसी योजनाओं पर भी कार्य आरंभ हुआ। यह सहयोग न केवल द्विपक्षीय ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करता है, बल्कि सार्क के "साझा ऊर्जा सुरक्षा" के सिद्धांत को भी व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। सुरक्षा और आतंकवाद–निरोधक नीति के क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश ने घनिष्ठ समन्वय स्थापित किया। सीमा पार आतंकवाद, अवैध घुसपैठ, मादक पदार्थों की तस्करी और उग्रवाद जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सुरक्षा एजेंसियों के स्तर पर निरंतर संवाद हुआ। बांग्लादेश ने भारत के पूर्वोत्तर में सक्रिय उग्रवादी समूहों पर प्रभावी कार्रवाई की, जिससे सीमा क्षेत्र में शांति बनी रही। इससे सार्क क्षेत्र में आतंकवाद–निरोधक सहयोग के लिए भारत–बांग्लादेश मॉडल प्रेरक सिद्ध हुआ।

हालाँकि, एनडीए शासनकाल में सार्क की सक्रियता में गिरावट देखी गई। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण भारत ने 2016 में इस्लामाबाद में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया। इसके परिणामस्वरूप सार्क लगभग निष्क्रिय हो गया। इसके बावजूद भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय स्तर पर सहयोग और अधिक गहराता गया। भारत ने अपनी रणनीति को "Selective

Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Research (JIMR)
E-ISSN:1936-6264| Impact Factor: 8.886| UGC CARE II
Vol. 20 Issue 09, Sep- 2025
Available online at: https://livejimrjournal.in/
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

Regionalism" की दिशा में मोड़ा– अर्थात् सार्क मंच के बजाय ठप्डैज्म्ब और प्व्। जैसे वैकल्पिक मंचों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू "सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी" भी रहा। भारत ने बांग्लादेश के साथ सांस्कृतिक, धार्मिक और मानवीय स्तर पर भी संबंधों को गहराई दी। 2021 में दोनों देशों ने मैत्री दिवस मनाकर अपने कूटनीतिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी की ढाका यात्रा ने यह संदेश दिया कि भारत–बांग्लादेश संबंध केवल रणनीतिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक बंधनों से भी जुड़े हैं। यह भावनात्मक जुड़ाव सार्क की सामाजिक एकता की भावना को भी पुष्ट करता है।

कोविड–19 महामारी के दौरान भारत ने दक्षिण एशिया में सहयोग की नई मिसाल पेश की। भारत ने "सार्क कोविड–19 आपात कोष (SAARC COVID&19 Emergency Fund)" की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिसमें बांग्लादेश सहित सभी सदस्य देशों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त भारत ने "Vaccine Maitri Mission" के तहत बांग्लादेश को कोविड–19 टीके और चिकित्सा सहायता प्रदान की। इस मानवीय पहल ने दक्षिण एशिया में भारत की सहयोगी छवि को सुदृढ़ किया और सार्क की मानवीय नीति को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया।

सार्क के औपचारिक मंच की निष्क्रियता के बावजूद, एनडीए शासनकाल में भारत– बांग्लादेश साझेदारी ने दक्षिण एशिया में स्थिरता और विकास की भावना को जीवित रखा। जहाँ यूपीए काल में संबंधों का स्वर भावनात्मक और संवादात्मक था, वहीं एनडीए काल में यह सहयोग अधिक रणनीतिक और व्यावहारिक रूप में विकसित हुआ। बांग्लादेश भारत की "Neighbourhood First" नीति का केंद्रीय स्तंभ बन गया, जिसने भारत के क्षेत्रीय नेतृत्व को मजबूती प्रदान की।

इस प्रकार, एनडीए शासनकाल में भारत–बांग्लादेश संबंधों ने सार्क की औपचारिक सीमाओं से परे जाकर क्षेत्रीय सहयोग का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया– ऐसा मॉडल जो द्विपक्षीय विश्वास, आर्थिक परस्परता और सुरक्षा सहयोग पर आधारित था। यद्यपि सार्क संगठन औपचारिक रूप से निष्क्रिय रहा, किंतु भारत–बांग्लादेश की सक्रिय साझेदारी ने यह सिद्ध किया कि दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय एकता की भावना अभी भी जीवित है और इसका पुनर्जीवन इन दोनों देशों के सहयोग पर ही निर्भर करता है।

यूपीए और एनडीए शासनकाल में भारत–बांग्लादेश सम्बन्धों पर सार्क पर प्रभाव का तुलनात्मक विश्लेषण

भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों ने वर्ष 2004 से 2022 तक के कालखंड में दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। इस अवधि के दोनों प्रमुख राजनीतिक शासन– यूपीए (2004–2014) और एनडीए (2014–2022) ने अपने–अपने दृष्टिकोण से इन संबंधों को नई दिशा दी। यद्यपि दोनों सरकारों का उद्देश्य समान था– क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास और सहयोग की भावना को सशक्त बनाना–किंतु उनके दृष्टिकोण, नीतिगत प्राथमिकताओं और कूटनीतिक शैली में उल्लेखनीय अंतर देखा गया।

यूपीए शासनकाल में भारत–बांग्लादेश संबंधों का आधार "विश्वास, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग" पर था। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने अपनी विदेश नीति को "Neighbourhood First" की भावना से निर्देशित किया, जिसके तहत भारत ने दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए सार्क को सक्रिय रखा। बांग्लादेश के साथ संबंधों में यह काल संवेदनशीलता और सहकारिता का प्रतीक रहा। इस दौरान सार्क फ्री ट्रेड एरिया (SAFTA), सार्क विकास कोष (SAARC Development Fund) और सार्क विश्वविद्यालय जैसी पहलों ने क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की दिशा में सकारात्मक योगदान दिया। बांग्लादेश को भारत से विद्युत आपूर्ति, व्यापारिक रियायतें और सीमा प्रबंधन सहयोग मिला, जिसने दोनों देशों के बीच विश्वास को पुनः स्थापित किया।

इसके विपरीत, एनडीए शासनकाल में भारत की विदेश नीति अधिक "रणनीतिक और सुरक्षा–केंद्रित" रूप में सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "Neighbourhood First" नीति ने संबंधों को व्यावहारिकता और भू–राजनीतिक दृष्टिकोण से पुनर्परिभाषित किया। वर्ष 2015 के भूमि सीमा समझौते (LBA) ने दशकों पुराने विवाद को समाप्त कर भारत–बांग्लादेश संबंधों को ऐतिहासिक ऊँचाई दी। भारत ने बांग्लादेश के साथ ऊर्जा, परिवहन, डिजिटल संपर्क और रक्षा सहयोग जैसे क्षेत्रों में ठोस प्रगति की, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध और गहरे हुए। हालाँकि, पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव और 2016 के इस्लामाबाद सार्क सम्मेलन के बहिष्कार के कारण सार्क की औपचारिक गतिविधियाँ ठप हो गईं।

दोनों कालों की विदेश नीति की प्राथमिकताओं में एक स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है। यूपीए काल में विदेश नीति का उद्देश्य था– संवाद और बहुपक्षीय संस्थाओं के माध्यम से क्षेत्रीय एकता को मजबूत करना; जबकि एनडीए काल में नीति का फोकस था– सुरक्षा, आतंकवाद–निरोध और रणनीतिक स्वायत्तता। यूपीए शासन में सार्क भारत की कूटनीति का केंद्र था, वहीं एनडीए शासन में भारत ने BIMSTEC, IORA और QUAD जैसे वैकल्पिक मंचों की ओर ध्यान केंद्रित किया।

फिर भी, दोनों कालों में भारत–बांग्लादेश साझेदारी सार्क के लिए शक्ति–स्रोत बनी रही। यूपीए शासनकाल में यह साझेदारी भावनात्मक और सहकारी थी, जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक निकटता पर आधारित थी। एनडीए शासनकाल में यह रणनीतिक और व्यावहारिक रूप में विकसित हुई, जो सुरक्षा, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय स्थिरता पर केंद्रित रही। दोनों ही कालों में भारत ने बांग्लादेश को अपनी "Neighbourhood Policy" के केंद्र में रखा, किंतु सार्क की भूमिका यूपीए काल में प्रमुख और एनडीए काल में परोक्ष बन गई।

यूपीए काल में भारत ने क्षेत्रीय एकता को बहुपक्षीय संस्थाओं के माध्यम से बढ़ाने का प्रयास किया, जबकि एनडीए काल में भारत ने द्विपक्षीय सहयोग को अधिक प्राथमिकता दी। उदाहरणस्वरूप, यूपीए ने सार्क मंच पर गरीबी उन्मूलन और सामाजिक विकास की योजनाएँ आरंभ कीं, वहीं एनडीए ने बांग्लादेश के साथ प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा, जल और व्यापार के समझौते किए। यूपीए काल की नीति में संवेदनशीलता और संतुलन था, जबकि एनडीए काल की नीति में साहसिक निर्णय और राष्ट्रीय हित प्रमुख रहे।

सार्क की दृष्टि से देखा जाए तो यूपीए काल में संगठन की सक्रियता और प्रासंगिकता बनी रही, क्योंकि भारत–बांग्लादेश साझेदारी ने इसे क्षेत्रीय सहयोग का ठोस मंच बनाया। वहीं एनडीए काल में सार्क की निष्क्रियता बढ़ी, परंतु भारत–बांग्लादेश संबंधों ने क्षेत्रीय सहयोग की भावना को अन्य वैकल्पिक मंचों

Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Research (JIMR)
E-ISSN:1936-6264| Impact Factor: 8.886| UGC CARE II
Vol. 20 Issue 09, Sep- 2025
Available online at: https://livejimrjournal.in/
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

पर जीवित रखा। इस प्रकार, दोनों कालों की नीतियों ने अलग–अलग मार्गों से दक्षिण एशिया में स्थिरता और सहयोग को प्रोत्साहित किया।

समानताओं की बात करें तो दोनों ही कालों में भारत ने बांग्लादेश को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के रूप में स्वीकार किया। दोनों कालों में आर्थिक और ऊर्जा सहयोग, सीमा सुरक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ किया गया। अंतर केवल दृष्टिकोण का रहा– यूपीए काल में सहयोग सार्क के माध्यम से बहुपक्षीय था, जबकि एनडीए काल में सहयोग द्विपक्षीय और रणनीतिक स्वरूप का रहा।

अंततः कहा जा सकता है कि भारत–बांग्लादेश साझेदारी दोनों कालों में दक्षिण एशिया की स्थिरता का आधार बनी रही। यूपीए शासन ने सार्क को सक्रिय रखकर क्षेत्रीय सहयोग का संस्थागत ढाँचा मजबूत किया, जबकि एनडीए शासन ने सार्क से परे जाकर व्यावहारिक कूटनीति के माध्यम से क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दिया। दोनों नीतियाँ अपने–अपने संदर्भ में सफल रहीं, और इनसे यह स्पष्ट होता है कि भारत–बांग्लादेश संबंध दक्षिण एशिया में किसी भी क्षेत्रीय एकता के लिए सबसे महत्वपूर्ण धुरी हैं।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य एवं भारत–बांग्लादेश साझेदारी की भविष्य दिशा

वर्तमान समय में भारत–बांग्लादेश संबंध दक्षिण एशियाई राजनीति के सबसे सशक्त स्तंभों में से एक हैं। वर्ष 2022 के बाद दोनों देशों के बीच संबंध न केवल स्थिर बने हुए हैं, बल्कि वे क्षेत्रीय रणनीतिक सहयोग के नए आयामों को भी छू रहे हैं। जहाँ सार्क संगठन राजनीतिक मतभेदों और पाकिस्तान की निष्क्रियता के कारण ठहराव की स्थिति में है, वहीं भारत और बांग्लादेश ने द्विपक्षीय और वैकल्पिक मंचों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग की भावना को जीवित रखा है। इस प्रकार, यह संबंध अब सार्क की सीमाओं से आगे बढ़कर दक्षिण एशिया की नई कूटनीतिक दिशा निर्धारित कर रहा है।

आज भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग बहुआयामी रूप ले चुका है– आर्थिक, ऊर्जा, जल, परिवहन, सुरक्षा, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्रों में गहरा संबंध स्थापित हो चुका है। दोनों देशों के बीच व्यापार 15 अरब डॉलर से अधिक पहुँच गया है, जिससे बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। सीमावर्ती क्षेत्रों में पारगमन मार्गों, रेल व सड़क संपर्कों तथा मित्रता सेतु (Maitri Setu) जैसी परियोजनाओं ने क्षेत्रीय संपर्क (connectivity) को अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ाया है। यह सहयोग दक्षिण एशिया के आर्थिक एकीकरण की दिशा में सार्क के मूल उद्देश्यों को अप्रत्यक्ष रूप से पूरा कर रहा है।

ऊर्जा क्षेत्र में भारत–बांग्लादेश साझेदारी दक्षिण एशिया के लिए एक मॉडल के रूप में उभरी है। दोनों देशों के बीच बिजली और गैस पाइपलाइन परियोजनाओं ने ऊर्जा निर्भरता को घटाया है और क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता को बढ़ाया है। बांग्लादेश अब भारत से प्रतिदिन लगभग 1,200 मेगावॉट बिजली आयात करता है, जिससे औद्योगिक विकास को नई गति मिली है। भारत ने भी बांग्लादेश के बंदरगाहों (चटगांव और मोंगला) तक पहुँच प्राप्त कर अपने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए व्यापारिक मार्गों को सुगम बनाया है।

रणनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत–बांग्लादेश सहयोग का महत्व चीन की "Belt and Road Initiative (BRI)" और दक्षिण एशिया में उसके बढ़ते प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में और भी बढ़ गया है। बांग्लादेश का भू–स्थान भारत के पूर्वोत्तर को दक्षिण–पूर्व एशिया से जोड़ने वाली "Act East Policy" का महत्वपूर्ण सेतु

Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Research (JIMR)
E-ISSN:1936-6264| Impact Factor: 8.886| UGC CARE II
Vol. 20 Issue 09, Sep- 2025
Available online at: https://livejimrjournal.in/
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

है। भारत ने इस नीति के अंतर्गत बांग्लादेश के साथ परिवहन, तकनीकी सहयोग और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में कई समझौते किए हैं। इन पहलों ने न केवल द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ किया है बल्कि क्षेत्रीय शक्ति–संतुलन को भी भारत के पक्ष में स्थिर किया है।

सांस्कृतिक और मानवीय दृष्टि से दोनों देशों के बीच निकटता निरंतर बढ़ रही है। "Vaccine Maitri Mission" के तहत कोविड–19 महामारी के दौरान भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गई सहायता ने दोनों देशों के बीच मानवीय विश्वास को और गहरा किया। इसके अतिरिक्त, शिक्षा, कला, संगीत, सिनेमा और पर्यटन के क्षेत्र में साझा पहलें चल रही हैं, जिनसे दोनों देशों के नागरिकों के बीच जन–जन का संपर्क सशक्त हुआ है। यह वही भावना है जिसे सार्क अपने सामाजिक–सांस्कृतिक सहयोग के माध्यम से साकार करना चाहता था।

वर्तमान समय में भारत–बांग्लादेश संबंधों की सबसे बड़ी विशेषता है– स्थायित्व और राजनीतिक निरंतरता। दोनों देशों में सत्तारूढ़ नेतृत्व के बीच संवाद और परस्पर सम्मान बना हुआ है। इससे यह संकेत मिलता है कि भविष्य में भी यह संबंध केवल द्विपक्षीय नहीं रहेंगे, बल्कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय व्यवस्था के पुनर्गठन में केंद्रीय भूमिका निभाएँगे।

भविष्य की दिशा में भारत–बांग्लादेश साझेदारी से कई संभावनाएँ उभरती हैं। पहला, यह संबंध सार्क के पुनर्जीवन की कुंजी बन सकता है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश की सक्रिय भूमिका ही दक्षिण एशिया को पुनः सहयोग के मार्ग पर ला सकती है। दूसरा, दोनों देश BIMSTEC और Indo–Pacific frameworks के माध्यम से क्षेत्रीय और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा सकते हैं। तीसरा, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी नवाचार जैसे क्षेत्रों में साझा पहलें क्षेत्रीय सतत विकास का आधार बन सकती हैं।

हालाँकि कुछ चुनौतियाँ भी बनी हुई हैं– अवैध आव्रजन, सीमा पार तस्करी, और जल–वितरण विवाद जैसे मुद्दे समय–समय पर तनाव पैदा करते हैं। फिर भी दोनों देशों की राजनीतिक परिपक्वता और संवाद–आधारित नीति इन समस्याओं को नियंत्रित करने में सक्षम रही है।

संक्षेप में कहा जाए तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत–बांग्लादेश संबंध दक्षिण एशिया की स्थिरता और एकता के केंद्र में हैं। ये संबंध अब केवल द्विपक्षीय नहीं, बल्कि क्षेत्रीय नेतृत्व और वैश्विक रणनीतिक सहयोग का प्रतीक बन चुके हैं। भविष्य में यदि सार्क को पुनर्जीवित करना है, तो भारत–बांग्लादेश की यह साझेदारी ही उस पुनर्जीवन की सबसे प्रभावी आधारशिला सिद्ध हो सकती है– क्योंकि दक्षिण एशिया का सहयोग वहीं से शुरू होता है जहाँ भारत और बांग्लादेश एक साथ खड़े होते हैं।

निष्कर्ष

भारत और बांग्लादेश के संबंध दक्षिण एशिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय स्थिरता के केंद्र में हैं। वर्ष 2004 से 2022 तक का काल दोनों देशों की साझेदारी और सार्क संगठन की दिशा के लिए अत्यंत निर्णायक रहा। इस अवधि में भारत की विदेश नीति ने दो अलग–अलग रूपों में विकास किया– यूपीए शासन के दौरान संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित, तथा एनडीए शासन के दौरान रणनीतिक और सुरक्षा–केंद्रित रूप में। दोनों ही चरणों ने अपनी–अपनी तरह से सार्क और दक्षिण एशियाई सहयोग की भावना को प्रभावित किया।

यूपीए शासनकाल (2004–2014) में भारत और बांग्लादेश के संबंधों ने विश्वास, संवेदनशीलता और सांस्कृतिक निकटता की नई मिसाल कायम की। मनमोहन सिंह सरकार ने सार्क को क्षेत्रीय संवाद, आर्थिक सहयोग और सामाजिक विकास का मंच बनाया। भारत ने बांग्लादेश के साथ ऊर्जा, व्यापार, शिक्षा और सीमा प्रबंधन के क्षेत्रों में कई ऐतिहासिक पहलें कीं। इन पहलों से न केवल द्विपक्षीय संबंधों में सुधार हुआ, बल्कि सार्क की सक्रियता को भी नई गति मिली।

एनडीए शासनकाल (2014–2022) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "Neighbourhood First" नीति के अंतर्गत भारत–बांग्लादेश संबंधों में और अधिक स्थायित्व आया। 2015 का भूमि सीमा समझौता (LBA) दोनों देशों के बीच विश्वास की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। आर्थिक संपर्क, ऊर्जा सहयोग और डिजिटल कनेक्टिविटी में तीव्र वृद्धि ने दक्षिण एशिया में नई संभावनाएँ खोलीं। यद्यपि पाकिस्तान के साथ तनाव और आतंकवाद की चुनौतियों के कारण सार्क निष्क्रिय हो गया, फिर भी भारत और बांग्लादेश की द्विपक्षीय सक्रियता ने क्षेत्रीय सहयोग की भावना को जीवित रखा।

दोनों कालों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यूपीए काल में भारत–बांग्लादेश साझेदारी भावनात्मक और संवाद–प्रधान थी, जबकि एनडीए काल में यह रणनीतिक और व्यावहारिक बन गई। यूपीए ने सार्क को बहुपक्षीय सहयोग का माध्यम बनाया, वहीं एनडीए ने सार्क के बाहर BIMSTEC और Indo–Pacific जैसे मंचों के माध्यम से सहयोग को आगे बढ़ाया।

आज भारत–बांग्लादेश संबंध दक्षिण एशिया की शांति, विकास और एकता के सबसे सशक्त स्तंभ के रूप में स्थापित हैं। ये संबंध यह प्रमाणित करते हैं कि सार्क की निष्क्रियता के बावजूद क्षेत्रीय सहयोग की भावना समाप्त नहीं हुई है, बल्कि उसने नए आयाम ग्रहण किए हैं। भविष्य में यदि सार्क को पुनर्जीवित करना है, तो भारत और बांग्लादेश की साझेदारी ही उस पुनर्जीवन की आधारशिला होगी।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत–बांग्लादेश संबंध केवल दो देशों की कूटनीतिक समझ नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया के सामूहिक विकास और स्थायी शांति का मार्गदर्शक सूत्र हैं। इन संबंधों में ही सार्क की पुनर्स्थापना, क्षेत्रीय एकता और "Shared South Asian Prosperity" की वास्तविक आशा निहित है।

संदर्भ

1. सिंह, मनमोहन. भारत की विदेश नीति और दक्षिण एशिया में सहयोग की दिशा. नई दिल्ली: प्रकाशन विभाग, 2010.

2. शर्मा, वीणा. भारत–बांग्लादेश संबंध : एक अध्ययन. जयपुर : आर्य पब्लिशिंग हाउस, 2018.

3. त्रिपाठी, अम्बरीश. दक्षिण एशिया में भारत की कूटनीति और सार्क की भूमिका. वाराणसी : विश्वभारती प्रकाशन, 2016.

4. गौतम, एस.पी. भारतीय विदेश नीति : दृष्टि, दिशा और विकास. नई दिल्ली : अटलांटिक पब्लिशिंग कंपनी, 2019.

5. मिश्रा, नरेश. भारत–बांग्लादेश सहयोग और सार्क का भविष्य. भोपाल : हिंदी ग्रंथ अकादमी, 2020.

6. Ministry of EÛternal Affairs] Government of India- India–Bangladesh Relations: Official Reports and Documents (2004–2022)- New Delhi: MEA Publications, 2023.

7. राघवन, वी.एन. India and South Asia: Regional Cooperation and Challenges. नई दिल्ली : मैनस पब्लिकेशन, 2017.

8. हुसैन, मोहम्मद. Bangladesh and South Asian Regional Politics. ढाका : बांग्लादेश यूनिवर्सिटी प्रेस लिमिटेड, 2018.

9. चतुर्वेदी, रुचि. भारत की पड़ोसी नीति : बांग्लादेश और सार्क के संदर्भ में. नई दिल्ली : सेज पब्लिकेशन, 2021.

10. Ministry of External Affairs. Annual Report (2014–2022). New Delhi: Government of India, 2022.

11. चौधरी, नीलम. "भारत–बांग्लादेश संबंधों का क्षेत्रीय सहयोग पर प्रभाव." विदेश नीति अध्ययन पत्रिका, खंड 15, अंक 2, 2020, पृ. 45–58.

12. बोस, सुमंत्रा. South Asia: State of Nations, Regional Cooperation and Conflict. लंदन : रूटलेज, 2019.

13. भट्टाचार्य, संजय. India*s Neighbourhood First Policy: A Strategic Appraisal. नई दिल्ली : पेंटागन प्रेस, 2021.

14. दासगुप्ता, अनुराधा. BIMSTEC और सार्क : भारत की क्षेत्रीय नीति का तुलनात्मक अध्ययन. कोलकाता : दीप पब्लिकेशन, 2022.